भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3789
(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

उच्च शिक्षा पर जीएसटी की कटौती और छात्रों की वित्तीय सुलभता

3789. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उच्च शिक्षा और शैक्षिक भुगतान पर जीएसटी दरों को कम करने से छात्रों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो सकता है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्च शिक्षा और संबंधित भुगतानों पर जीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत, 5 प्रतिशत या 0 प्रतिशत स्लैब में लाने पर विचार किया है;
(ग) यदि नहीं, तो शैक्षिक सेवाओं पर वर्तमान जीएसटी दरों को बनाए रखने के क्या कारण हैं; और
(घ) क्या शिक्षा क्षेत्र के लिए जीएसटी सुधारों के संबंध में हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया गया है, विशेषकर सांगली जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों के छात्रों पर वित्तीय बोझ को संबोधित करने के लिए, जहां उच्च शिक्षा तक पहुंच पहले से ही आर्थिक कारकों से बाधित है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) से (घ): जीएसटी दरें और छूटें जीएसटी परिषद जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों सरकारों के सदस्य शामिल होते हैं, की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। दरें/छूटें या अन्यथा में बदलाव के बारे में कोई भी निर्णय जीएसटी परिषद की विचार-विमर्श प्रक्रिया के बाद ही लिया जाता है। वर्तमान में, शहरों की श्रेणी के आधार पर कोई अलग-अलग जीएसटी दरें प्रभावी नहीं हैं।
वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र को जीएसटी रूप-रेखा के तहत प्रदान की गई विभिन्न छूटें निम्नानुसार हैं:
क. अधिसूचना संख्या 12/2017 - केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017
1. क्रम संख्या 66:
क. किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों, संकाय और कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं;

ख. प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।

ग. किसी शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित सेवाएं:

i. ऐसी संस्था में प्रवेश या परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सेवाएं;

ii. यदि प्री-स्कूल या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक प्रदान की जाती हैं:

- छात्रों, संकाय और कर्मचारियों का परिवहन;
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना सहित खानपान;
- ऐसे शैक्षणिक संस्थान में की जाने वाली सुरक्षा या सफाई या हाउसकीपिंग सेवाएं;

iii. ऑनलाइन शैक्षिक पत्रिकाओं या सामयिक पत्रिकाओं की आपूर्ति (उच्च शिक्षण संस्थान को प्रदान की गई);

"शैक्षणिक संस्थान" को निम्नलिखित माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था के रूप में भी परिभाषित किया गया है,-

(i) प्री-स्कूल शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा;

(ii) फिलहाल लागू किसी भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा;

(iii) अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा;

2. क्रम संख्या 66 क: केन्द्रीय या राज्य शैक्षिक बोर्ड या परिषद या किसी अन्य समरूप निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित स्कूल को प्रदान की गई संबद्धता सेवाएं।

ख. अधिसूचना संख्या 02/2017 - केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 विभिन्न वस्तुओं को छूट प्रदान करती है, जो निम्नानुसार हैं:

1. ब्रेल पुस्तकों सहित मुद्रित पुस्तकें
2. समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और सामयिक पत्रिकाएँ, चाहे सचित्र हों या नहीं या जिसमें विज्ञापन सामग्री हो
3. बच्चों की चित्र, ड्राइंग या रंग भरने वाली पुस्तकें
4. स्लेट पेंसिलें और चॉक स्टिकस
5. स्लेट्स

वर्तमान में, किसी अन्य शैक्षणिक सेवा के लिए छूट या स्पष्टीकरण के संबंध में जीएसटी परिषद की ओर से कोई सिफारिश नहीं की गई है।

*****